(ख) चालू वर्ष के प्रथम आठ महीनों में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं की औसत माह-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे पर हुई गाड़ी दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की 70% घटनाएं हुई।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं की औसत संख्या प्रतिमाह 2.4 थी।

(ग) रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के मुख्य कारण मानव और उपस्कर विफलताएं, आकस्मिक कारक, आदि होते हैं।

(घ) भारतीय रेलों पर रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) भारी पटरियों और कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग करके रेलपथ अवसंरचना में सुधार करना।

(ii) अनुरक्षण में सुधार करने के लिए और परिसंपत्तियों की बेहतर विश्वसनीयता के लिए फिश प्लेटों के जुड़नारो को हटाया जा रहा है तथा लम्बे झले हुए पटरी पेनलों पर रनिंग रेलपथ बिछाया जा रहा है।

(iii) विभिन्न खंडों में रेलपथ नवीकरणों को बढ़ाना तथा मिट्टी संबंधी कमियों को दूर करना।

(iv) रेल पटरियों में छिपी हुई दरारों का पराश्रव्य दोष संसूचकों का उपयोग करके पता लगाना।

(v) चल स्टाक की नेगी ओवर हालिंग (आर०ओ०एच०) करने के लिए अव-संरचना का उन्नयन तथा संवर्धन करना तथा सवारी और मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का मानकीकरण करना।

(vi) निरंतर संरक्षा अभियान चलाना। 10 वर्ष से कम की सक्रिया चालन सेवा वाले लगभग 17,000 ड्राइवरों और 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की विशेष स्क्रीनिंग की गई है और जिनमें कमी पाई गई है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण दिया गया है।

(vii) संवेदनशील और भेद्य खंडों में गश्त में तेजी लाना।

(viii) धीरे-धीरे चौपहिए मालडिब्बों को हटाया जा रहा है और इनके स्थान पर बोगी स्टाक को लगाया जा रहा है।

नई दिल्ली के मन्दिर मार्ग स्थित एन०डी०एम०सी० वर्कशॉप परिसर में निर्माणों का गिराया जाना

800. **श्री अनन्तराम जयसवाल:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के आगमन की सूचना प्रसारित कर, नई दिल्ली के मन्दिर मार्ग पर स्थित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् परिसर में बने सभी मकानों को गिराकर अन्यत्र स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का आदेश दिए जाने का क्या उद्देश्य था इन मकानों को गिराने में सरकार ने कितनी राशि खर्च की;

(ग) क्या उक्त भूमि की उपयोगिता तय करने के लिए दिल्ली के उपायुक्त के नेतृत्व में कोई समिति गठित की गई थी और क्या सरकार को उक्त समिति के निर्णय से अवगत कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर परिषद ने बताया है कि 1.8 एकड़ भूमि पर ऑटो-वर्कशॉप का कब्जा है और आटो वर्कशाप कार्यों को स्थानान्तरित करने के लिए वैकल्पिक स्थलों को सुझाव देने हेतु उप-आयुक्त दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और ऑटो वर्क-शाप कार्यों को स्थानान्तरित करने के लिए सराय काले खॉ में भूमि

आवंटित कर दी गई है।

रेलवे की खाली पड़ी जमीन

801. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के आस-पास कितने एकड़ जमीन खाली पड़ी है;

(ख) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों के आस-पास रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर भू-माफिया द्वारा झुग्गियां बसाने के प्रयास से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस खाली पड़ी जमीन को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) 118.07 एकड़;

(ख) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है;

(ग) अतिक्रमणों के मामलों में बेदखली के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखल अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है वृक्षारोपण, चारदीवारी के निर्माण आदि जैसे रोधक उपाय भी किए जा रहे हैं;

(घ) रेलवे की खाली भूमि का उपयोग, अवसंरचना के विकास तथा परिचालनिक सुविधा और यात्री सुख-सुविधा संबंधी कार्यों में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा;

Survey Regarding Implementation of Command Area Development Programme

802. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have made any State-wise survey regarding the implementation of Command Area Development Programme;

(b) if so, the progress made in each State during the Eighth Plan; and

(c) the steps taken to bring more areas under irrigation through effective implementation of Command Area Development Programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Central Government reviews the State-wise implementation of Command Area Development Programme. The progress made in each State in respect of core components of Command Area Development Programme during the Eighth Plan upto 31-3-95 is given in statement (*see* below).

(c) For the effective implementation of Command Area Development Programme, monitoring efforts have been intensified, farmers' participation in the management of irrigation has been encouraged and training programmes for farmers and functionaries conducted. Further to identify the constraints in implementation of the Programme, 18 Evaluation studies have been awarded.

Statement

(*Unit*='000 hectare)

S. No.	Name of State	Total achievement 1992-93 to 1994-95			
		Field channels	Field Drains	Warabandi	Land Levelling
1.	Andhra Pradesh	5.60	0.00	44.58	10.32
2.	Arunachal Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Assam	4.04	2.12	8.30	0.00
4.	Bihar	41.15	0.00	4.04	0.00
5.	Goa	2.57	0.01	4.90	0.10
6.	Gujarat	40.22	0.35	57.36	0.56